ACTION FOR CHANGE – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS(FAQs) on Taxation and civic services reforms model presented at site www.actionforchange.co.in

Although the reforms suggested at site are the result of self less love and affectionate labour of few members of general public , yet it need the acumen of economic and financial experts. All experts of Government are invited to formalize the model. And once the reforms are formalized many FAQs will loose their relevance. Still even for experts the following may pave way to expedite work on reforms.

1. Why is it necessary to change the present taxation system of the country?

Ans. Most Important but challenging task is to change the present taxation system.And it is necessary because see –

how funds remain short with Govt. for welfare services &
How scams & pilferages takes place?

Under present taxation- Taxes are so many and there is rampant evasion thereby. Through excessive indirect taxes Govt. collect huge taxes, but whole goes up at treasury-
Suppose Rs. 300 crore collected- out of 600 crore probable tax collections

Now Govt. has 300 crore as taxes	AND	Public has 3000 crore(if avg. tax is 10%) as unaccounted money.
Govt. budgets to spend 200 crore on Developmental projects th. Subsidy etc. And rest 100 crore on welfare schemes for cities,Villages and poor. Subsidy leads to scams & Flow of funds from top to bottom leads to pilferage. So public and Leaders possess a portion of taxes as unaccounted Money.		Public plans to use this in Jewellery, Valuables, real estate and excessive movable assets and money gets blocked. The money is also used to pay bribes for obtaining Contracts and for getting works done illegally or out of turn. So Govt. officers, leaders also possess unaccounted money.

THUS the changes necessary are - To plug loopholes in collection &
- To check excessive blockade of money in unconstructive products & Properties.

THIS can be done only if -1. TAXABLE UNITS are in the count of GOVT. (identifiable);
2. Movable & Immovables are highly taxed; AND
3. Spendings by Govt. are transparent even to poor.

The abovesaid all three essentials can be achieved only by converting Municupality offices into Civic Centres as envisaged in 'The Civic Services Act' and giving them power to collect taxes.

2. क्या वर्तमान कर प्रणाली का automation(कम्पयूटरीकरण) और निरंतर किए जाने वाले सुधार अर्थव्यवस्था और अनपढों के उत्थान के लिए काफी नहीं है ?

उ. अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या है – नव निर्मित भवनों , सडकों , विद्यालयों या उनका सामान , हस्पतालों या उनका सामान और पटरियॉं आदि का निम्न स्तरीय निर्माण या पूर्ति और बेहद बुरा रख्र - रखाव और साथ ही उन पर होने वाला अवांछित अधिग्रहण(encroachment) या छीजन (embezzlement) । ये दोनों ही समस्याऐं कैसे automation से ठीक हो सकती हैं । इनके लिए तो नजदीकी देखरेख , नियंत्रण और तुरत सजा या दंड ही हल है ।
इसी प्रकार अनपढों के लिए तो अच्छी शिक्षा का अभाव और स्कूल छूट जाने पर अच्छे प्रशिक्षण का अभाव ही मुख्य समस्या है । इनके लिए भी नजदीकी देखरेख , नियंत्रण और तुरत सजा या दंड ही हल है ।ये दोनों ही कैसे automation से ठीक हो सकती हैं ।

3. सभी करों के एकदम से समाप्त करने का बकाया कर राशि और लंबित कर विवादों पर क्या प्रभाव होगा ?
उ. नये कर विवाद उत्पन्न नहीं होने से कानून को पुराने वितीय विवादों को एक छूट योजना के तहत निपटाने के लिए एक समय सीमा दी जा सकती है । कर प्रणाली सरल होने से लोगों के पास देय कर देने के लिए पैसा भी होगा । The experts can lay down a well planned switch over system.

4. लोक सेवा संस्थायें एक राज्य में बहुत ज्यादा हो जाने से उनमें समन्वय कैसे होगा ?
उ. एक तो उनमें समन्वय और नियंत्रण के लिए लोक सेवा मंडल (Board) या राज्य सरकार का लोक सेवा विभाग होगा । दूसरे वर्तमान में भी अगर PWD, MCD और राजस्व विभागों को मिलायें तो उनकी संख्या सेवा संस्थायों से ज्यादा ही होगी ।

5. क्या निजी क्षेत्र के हाथ में कर संग्रहण आने से और ज्यादा लूट खसोट तो नहीं होगी ?
उ. सेवा संस्था पूर्ण रूप से सरकारी होगी और क्षेत्र सीमित होने से और मासिक विवरणी में संग्रहण डाटा आने से और जनता का चैक होने से कर नियंत्रण – नियमन कोई मुश्किल कार्य नहीं होगा । On line कर जमा को RBI/SBI भी आसानी से नियंत्रित एवं वितरित कर सकता है ।

6. सकल बिक्री या प्राप्ती पर कैसे नियंत्रण होगा ?

   उ. एक तो सेवा संस्था का क्षेत्र सीमित होने से और मासिक विवरणी में बिक्री /प्राप्ती डाटा आने से और साथ ही साथ यहीं करों का मुख्य आधार होने से , प्रोफैश्नलस (CA, CS, CWA) के प्रमाण्न पर कढा नियंत्रण हो पायेगा । समय समय पर C.A.G द्वारा जाँच होने से यह नियंत्रण सुद्रढ़ होगा । बड़ी हेरा फेरी को जनता भी पकड़ पायेगी ।

7. एक अविकसित क्षेत्र का विकास कैसे होगा ?

   उ. केन्द्र के पास इसी बात का मुख्य नियेत्रण होगा । राज्य उस क्षेत्र का विकास अपने पास बची निधी से करेगा । पास के क्षेत्रों में जँहा समान विकास नहीं हुआ है – कुछ संस्थायें /उदयोग ज्यादा है तो उन्हें उस क्षेत्र में स्थानांत्रित किया जा सकता है । इसी प्रकार वँहा की लोक सेवा संस्था सुझाव देगी और कार्य करेगी । हर सेवा संस्था के अंर्तगत एक विकसित नगर या क्षेत्र भी सुनिष्चित किया जा सकता है ।

8. एक व्यक्ति जिस के पास एक बड़ा मकान है पर आय मात्र 10000 महीना है , वह कैसे कर देगा ?

   50 वंग गज के मकान पर छूट है । अगर जरूरत से ज्यादा है तो वह बेचेगा या किराये पर उठायेगा । अगर परिवार बड़ा है तो लोक सेवा संस्था सुझाव देगी और हल निकालेगी ।

9. पहले से जमा नगद पूंजी , सोना , चांदी आदि का क्या होगा ?

   उ. नयी कर व्यवस्था में नगद आदि कँहा से आया जैसा कोई प्रश्न ही नहीं है । इसीलिए नगदी को बेरोकटोक बैंक में जमा किया जा सकेगा । और यह व्यक्ति के लिए आवश्यक भी होगा क्योकि सर्किय बिल व्यवस्था होने से व्यापारी को खरीद सफेद धन से ही करनी होगी। अधिक सोना चॉदी को बिल से ही बेचा जायेगा तो पैसा अपने आप अर्थव्यवस्था में आएगा ।

********** x **********